ment in comparison to India as China offers preferential taxation treatment to the foreign investors and the Government procedure being simple causing least trouble to the foreign investors so that they could immediately begin implementing their projects;

(b) if so, what remedial action Government have taken or propose to take to attract more FDI in the country; and

(c) whether Government propose to review all the outdated existing procedures and remove them immediately to attract more FDI in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) to (c) Yes, Sir. The various policy initiatives detailed in the Statement on Industrial Policy, 1991 and other economic liberalizations announced by Government, are aimed, inter-alia, at attracting larger foreign investment in the country. Since the announcement of these policy initiatives, there has been considerable buoyancy in approvals granted for foreign direct investment in the country. As against the proposals envisaging foreign direct investment of Rs. 128.32 crores in 1990 and Rs. 534.11 crores in 1991, the foreign direct investment approved in 1992 was Rs. 3887.54 crores and Rs. 3951.96 crores during the current year upto June.

Government constantly review the policy framework for foreign investrors to ensure that India can compete effectively with countries that have been successful in attracting foreign investment.

मारूति उद्योग लिमिटेड द्वारा कारों के उत्पादन के लिए निर्धारित किया गया लक्ष्य

594. **श्री अनन्त राय देवशंकर दवे**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारूति उद्योग लिमिटेड ने अगले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न मैक की अपनी कारों के उत्पादन के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) क्या मारूति उद्योग लिमिटेड ने अपने विस्तारीकरण की कोई कार्य योजना सरकार के समक्ष प्रस्तुत की है, और सरकार द्वारा कितनी धनराशि के शेयर बेचे गये हैं; इसके परिणामस्वरूप कम्पनी को कितना घाटा हुआ है;

(ग) क्या मारूति उद्योग लिमिटेड ने पूंजी बाजार से संसाधन जुटाने के लिये सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और क्या यह अन्तर्राष्ट्रीय ऋण बाजार से संसाधन जुटाने के लिये भी प्रयत्नशील है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) मारूति उद्योग लिमिटेड (एम॰ यू॰ एल॰) ने अपनी उत्पादन क्षमता 1,30,000 से बढ़ाकर 2,00,000 वाहन प्रति वर्ष करने हेतु एक विस्तारीकरण योजना शुरू की है और 1995-96 तक क्षमता में वृध्दि हो जाने की संभावना है । वाहनवार उत्पाद-मिश्र प्रत्येक वर्ष के लिए बाजार की मांग पर निर्भर करेगा ।

(ख) मारूति उद्योग लिमिटेड ने क्षमता विस्तार के लिए अपनी परियोजना रिपोर्ट सरकार को फरवरी, 1991 में प्रस्तुत की थी, जिसे सरकार द्वारा जून, 1992 में अनुमोदित कर दिया गया । चूंकि अब मारूति उद्योग लिमिटेड सरकारी कम्पनी नहीं है, अत: यह अपनी कार्रवाई योजनाएं सरकार को प्रस्तुत नहीं करती ।

सरकार ने अब तक 100 रुपये प्रत्येक के 34,400 इक्विटी शेयर मारूति उद्योग लिमिटेड कर्मचारी सहयोग निधि को बेचे हैं जिनका ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है;

क्रम सं॰	शेयरों की संख्या	प्रत्येक शेयर बिक्री मूल्य	बिक्री की तारीख
1.	26,600	176 रुपये	29-4-91
2.	7,800	211 रुपये	18-5-92

कम्पनी को इसके कारण कोई घाटा नहीं हुआ है ।

(ग) और (घ) मारूति उद्योग लिमिटेड ने पूंजी बाजार से निधियां जुटाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है । तथापि, अपनी इक्विटी में बढ़ोतरी के लिए यह अनेक विकल्पों पर विचार कर रही है । मारूति उद्योग लि॰ ने 220 करोड़ रुपयों के बराबर विदेशी मुद्रा ऋण के लिए जापान के निर्यात आयात बैंक से भी सम्पर्क किया है ।

Expansion of PSUs in Gujarat

595. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE:
SHRI GOPAL G. SOLANKI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have received any proposals for expansion of the existing public sector undertakings in Gujarat for the years 1993-94 and 1994-95;